इकाई- 5

5

रोजगार एवं सेवाएँ

सेवा क्षेत्र में रोजगार का महत्त्व काफी अधिक है । रोजगार से हमारा अभिप्राय देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना है जिससे देश की उत्पादकता बढ़ सके और सामान्य जन मानस के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकतायें रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त हो सके । विश्व के प्रत्येक देश के सरकार का प्रथम प्रयास यह होता है कि वहाँ के उपलब्ध मानव संसाधन को उनकी दक्षता के आधार पर काम उपलब्ध कराया जा सके । ऐसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं और जिन्हें उचित पारिश्रमिक पर काम नहीं मिलता, उन्हें बेरोजगार कहा जाता है । देश के ऐसे लोग जो स्वेक्षा से काम करना नहीं चाहते उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जाना अर्थात उचित पारिश्रमिक पर सक्षम रूप से काम करने वालों को यदि काम न मिले तो उसे बेरोजगार कहते हैं। भारत में योजनात्मक विकास के क्रम में सेवा क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ है जिसके कारण बेरोजगारी में कमी आई है । सेवा क्षेत्र से हमारा तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहाँ शारीरिक शक्ति, कार्यक्षमता और दक्षता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाय । भारत में कृषि लोगों के रोजगार उपलब्ध करने का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है, इसके साथ-ही-साथ उद्योग व्यवसाय, स्वास्थ्य, यातायात आदि ऐसे क्षेत्र जिससे लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ मिलती हैं ।

रोजगार एवं सेवाएँ

''रोजगार एवं सेवाएँ'' का अभिप्राय यहाँ पर इन बातों से है जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीवकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है । एकत्रित धन को जब पूँजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है । अतः रोजगार एवं सेवाएँ एक दूसरे के पूरक हैं । अर्थात् रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होता है ।

आर्थिक विकास का क्षेत्र

रोजगार एवं सेवाएँ आर्थिक क्रियाओं के विकास और विस्तार से उपलब्ध होती है । इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक प्रगति के कारण देश के विकास के साथ सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है जिसके फलस्वरूप लोगों के लिए रोजगार के नये-नये अवसर उपलब्ध होने लगते हैं ।

आर्थिक विकास के मुख्य रूप से तीन क्षेत्र हैं- (क) कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) (ख) उद्योग क्षेत्र (Industrial Sector) तथा (ग) सेवा क्षेत्र (Service Sector) ।

आर्थिक विकास के क्षेत्र

(क) कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector)

(ख) उद्योग क्षेत्र (Industrial Sector) तथा

(ग) सेवा क्षेत्र (Service Sector)

(क) कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector)-भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का लगभग 67 प्रतिशत बोझ है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्षीण हो गया है। फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में 'छिपी हुई बेराजगारी' एवं अन्य बेरोजगारी पाए जाने लगे हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ खेती-बारी के लिए जमीन में वृद्धि नहीं हो पा रहा है और एक ही भूखण्ड पर आनेवाली नई पीढ़ी भी जुटता चला जा रहा है जिससे उत्पादन की मात्रा प्रति व्यक्ति पर घटता चला जा रहा है।

(ख) उद्योग क्षेत्र (Industrial Sector)- रोजगार का दूसरा क्षेत्र 'उद्योग क्षेत्र' है । इस क्षेत्र के माध्यम से भी रोजगार की प्राप्ति की जा रही है । देश की औद्योगिक विकास की गति में तेजी आने के द्वारा ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होती है ।

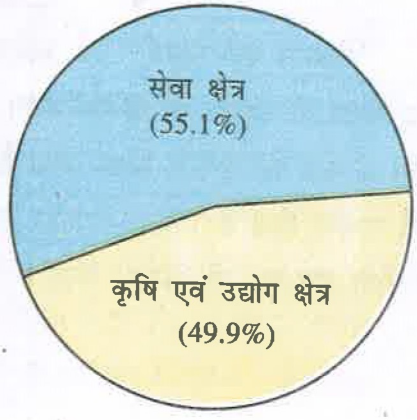

(ग) सेवा क्षेत्र (Service Sector)- आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है । सेवा क्षेत्र रोजगार

का एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आये दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं । वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में सेवा क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया है । आर्थिक समीक्षा 2006-07 और केन्द्रीय बजट 2007-08 के अनुसार सेवा क्षेत्र का यह योगदान 68.6 प्रतिशत हो गया है । 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का हिस्सा घटकर 18.5 प्रतिशत उद्योग का हिस्सा बढ़कर 26.4 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का 55.1 प्रतिशत हो गया है।

उपरोक्त आँकड़े इस बात का संकेत देता है कि अब हमारे देश में विकास की गति में तेजी आने लगी है ।

सेवा क्षेत्र की भूमिका

विश्व के विकसित देशों की तुलना में अर्द्धविकसित और विकासशील देशों में गरीब बेराजगारों की संख्या अत्यधिक है । कहा तो यह जाता है कि विश्व की संख्या का दो-तिहाई भू-भाग गरीबी और विपन्नता से ग्रस्त है । अर्द्धविकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या का आधिक्य होता है तथा वहाँ उत्पादन के अन्य साधन पूर्णतः उपलब्ध नहीं होते हैं जिसके कारण वहाँ बेराजगारी की समस्या उत्पन्न होती है । सेवा क्षेत्र के विकास से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं । सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मनुष्य को शिक्षित करना नितांत आवश्यक है । जिस देश या राज्य की मानव पूँजी जितना ही समृद्ध होता है उस देश या राज्य का आर्थिक विकास उतना ही तीव्र गति से होता है । समृद्ध मानव पूँजी एक सशक्त श्रम शक्ति को जन्म देता है जिसके कारण लोग रोजगार पाने में सक्षम हो पाते हैं तब लोग हीन भावना से ऊपर उठकर देश व राज्य के हित में काम करना प्रारंभ करते हैं जिससे विकास की स्थिति पैदा होती है ।

यह कहना अप्रसांगिक नहीं होगा कि विश्व के सर्वाधिक विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इंगलैंड के सेवा क्षेत्र के विस्तार में भारतीय मूल के दक्ष मानव संसाधन की प्रमुख भूमिका नहीं है । यदि भारत में भी उच्च कोटी के उत्पादन क्षेत्रों को कारगर किया जाए वे यहाँ के उपलब्ध मानवीय संसाधानों के द्वारा आर्थिक विकास की गति को और अधिक तेज किया जा सकता है । कहा तो यह भी जाता है कि भारत के मानवीय संसाधन विश्व के "सर्वश्रेष्ठ

मानवीय संसाधनों" में आते हैं।

बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है जो वर्षों तक गरीबी और बेराजगारी का केन्द्र रहा है। देश के अन्य राज्य जैसे-उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था विकास की ओर तेजी से उन्मुख नहीं हो सका है। विगत कुछ वर्षों में बिहार में आर्थिक प्रगति दिखने लगा है। जैसे-सड़क का विस्तार एवं स्वास्थ्य सेवाएँ का प्रसार। पिछले दिनों बाढ़ की विभीषिका और सूखे के कारण जो विपरीत परिस्थिति आई है उससे बिहार के विकास कार्य को एक बड़ा झटका लगा है फिर भी दूर संचार सेवाएँ, यातायात सेवाएँ, चिकित्सा सेवाएँ, शिक्षा सेवाएँ, ब्यूटी पॉर्लर की सेवाएँ, स्वरोजगार की सेवाएँ इत्यादि की व्यापक प्रसार के कारण बिहार में सेवा क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ है। राज्य स्तर पर सेवा क्षेत्र की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है जिससे काफी लोग लाभांवित हुए हैं और हो रहे हैं।

सेवा क्षेत्र का भाग

सेवा क्षेत्र को सामान्यतः दो भागों में विभक्त किया जाता है- (क) सरकारी सेवा (ख) गैर सरकारी सेवा ।

(क) सरकारी सेवा- जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। सरकारी सेवा के कुछ व्यापक क्षेत्र का उदाहरण इस प्रकार है- सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा इत्यादि ।

सरकारी सेवा क्षेत्र

1. सैन्य सेवा	2. शिक्षा सेवा
3. रेल सेवा	4. बस सेवा
5. वायुयान सेवा	6. कृषि सेवा
7. स्वास्थ्य सेवा	8. अभियंत्रण सेवा
9. वित्त सेवा	10. बैंकिंग सेवा
11. अन्य सरकारी सेवाएँ	

(ख) गैर सरकारी सेवा- जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों

तक पहुँचाने का काम करती है अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभांवित होते हैं तो उसे गैर सरकारी सेवा को जाता है । इस क्षेत्र के भी कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं- बैंकिंग सेवा, दूरसंचार सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार सेवाएँ इत्यादि । इनमें से कुछ सेवाएँ ऐसी है जो सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर चलाई जाती है । खासकर यातायात सेवाएँ, शिक्षा सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ, दूरसंचार सेवाएँ, बैंकिंग सेवाएँ इत्यादि का क्षेत्र इतना व्यापक है कि सरकार अकेले सक्षम नहीं है ।

सेवा क्षेत्र का भाग

(क) सरकारी सेवा

(ख) गैर सरकारी सेवा

गैर सरकारी सेवा क्षेत्र

1. बैंकिंग सेवा
2. दूरसंचार सेवा
3. यातायात सेवा
4. स्वास्थ्य सेवा
5. स्वरोजगार सेवाएँ
6. अन्य गैर सरकारी सेवाएँ

गोबिन्दपुर गाँव की कहानी

सुरेश अपने माता-पिता के साथ गोबिन्दपुर गाँव में रहता था । यह गाँव बिहार राज्य के नवादा जिला का है । सुरेश अपने चार भाइयों में सबसे बड़ा है । बड़ा होने के कारण परिवार के प्रति इसका दायित्व अधिक है। सुरेश के अन्य भाइयों का नाम जवाहर, हीरा एवं आशुतोष हैं । इस परिवार का मुख्य पेशा दुकानदारी करना है । गाँव में दुकान होने के कारण लोगों के जरूरत मन्द वस्तुएँ मिल जाती है । सुरेश मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास कर आगे की पढ़ाई करना चाहता था । परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण पढ़ाई बाधित होने को दिख रहा था । तभी सुरेश ने मन बनाया लिया कि शहर जाकर मैं ट्यूशन पढ़ाकर आगे की पढ़ाई करूँगा । सुरेश गाँव से आगे की पढ़ाई के लिए कर गया शहर आ गया। यहाँ इसने किसी तरह अपना नाम गया कॉलेज, गया में करा लिया। खुद पढ़ाकर पढ़ने की तमन्ना इसने साकार किया । परिश्रम ने भी सुरेश को साथ दिया। सुरेश प्रथम श्रेणी से इण्टर पास किया । पुनः इसने स्नातक डिग्री हासिल किया । नौकरी के लिए इसने तलाश करना शुरू कर दिया । यहाँ पर भी सुरेश ने सफलता प्राप्त की और वित्त सेवा में पदाधिकारी बन गया । अब सुरेश के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। इसने अपने अन्य भाइयों को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगा । भाइयों

ने भी काफी परिश्रम किया और एक सेना में, दूसरे ने प्रशासनिक सेवा एवं तीसरे ने अभियंत्रण सेवा प्राप्त करने में सफल रहा। आज सुरेश का परिवार काफी शिक्षित श्रेणी में माना जाता है। सुरेश के पिता आज के दिनों में दुकानदारी करते हुए भी एक "टेलीफोन बुथ" चलाते हैं। इस प्रकार सुरेश का परिवार विभिन्न सेवाओं से अपने आप को जोड़ लिया। इनके सेवाओं का लाभ अन्य लोगों को भी प्राप्त होने लगा। इस प्रकार समाज में सेवा क्षेत्र के विस्तार के कारण ही सुरेश के परिवार के लोगों को काम मिला और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई।

सेवा क्षेत्र का महत्त्व

सेवा क्षेत्र का महत्त्व रोजगार प्राप्ति में काफी है। सेवा एवं रोजगार एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों पक्षों को एक ही तराजू के दो पलड़ों के रूप में देखना होगा। अर्थात् इन्हें दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सेवा क्षेत्र का हम जितना ही विस्तार करेंगे रोजगार का अवसर उतना ही बढ़ेगा। उदाहरण स्वरूप मान लिया कोई किसान अपने खेतों में धान उपजाता है उसमें मेहनत कर चावल प्राप्त करता है। अगर वह किसान अपने घर में चावल को चुनकर एवं उसे साफ सुथरा कर एक किलो का पोलिथिन पैकेट बनाकर बाजार में अच्छे दाम पर बेचने का कार्य करता है तो उसे प्रारंभ से लेकर अंत तक रोजगार भी मिल जाता है और व्यापार करना चाहे तो इसे व्यापक स्तर पर भी कर सकता है, जिससे अधिक-से-अधिक लोगों को यह किसान रोजगार मुहैया करा सकता है। यदि किसान इससे संबंधित तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तो अपनी आमदनी को और अधिक बढ़ा सकता है। उपरोक्त उदाहरण से सामान्यत: दो बातें स्पष्ट होती है- पहला जब किसान अपने उत्पाद को अपने श्रम एवं दक्षता के कारण उसके गुणवत्ता में वृद्धि करता है तो उससे रोजगार के नए आयाम खुलते हैं जिससे भी सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। दूसरा जब वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है तो इससे उसे ऊँची कीमत पर बेचा जा सकता है। उत्पाद में गुणवत्ता के इस वृद्धि को (Value Added) कहते हैं।

रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की भूमिका

सेवा का क्षेत्र सरकारी हो अथवा गैर सरकारी दोनों ही परिस्थितियों में रोजगार का सृजन होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों की आवश्यकताएँ प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विस्तार हो रहा है। नये-नये कल-कारखाने खोले जा रहे हैं। इन कल-कारखानों को चलाने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाएँ का विकास किया जा रहा है। इन संरचनाओं के विकास के लिए हमें प्रशिक्षित, अर्द्धप्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षितों की आवश्यकता होती है। यही प्रशिक्षित, अर्द्धप्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित लोग मानव पूँजी के धरोहर होते हैं। मानव पूँजी को सबल एवं चुस्त-दुरुस्त बनाने हेतु हमें शिक्षा क्षेत्र के विकास पर व्यापक स्तर पर प्रयास करना पड़ता है। जितना ही शिक्षा का स्तर मजबूत होगा उतना ही अधिक मात्रा में मानव बल का प्रयोग आधुनिक उद्योग-धंधों में किया जाएगा, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल होगा।

चित्र 5.1 राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन करने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है । देश में सरकार के द्वारा रोजगार हेतु निम्न प्रकार की योजनाएँ चलायी जा रही है। सरकार के द्वारा चलायी गई

योजनाओं और उसके प्रारंभ होने के वर्षों को नीचे दिखाया जा रहा है :

- काम के बदले अनाज - (14 नवंबर 2004)
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम-(1980)
- ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम-(1979)
- ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम-(1983)
- समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम-(20 अक्टूबर 1980)
- जवाहर रोजगार योजना- (1989)
- स्वयं सहायता समूह
- नरेगा इत्यादि ।

उपर्युक्त सेवाओं के माध्यम से देश के बेराजगारी की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का अनुमान है कि देश के बेरोजगार लोगों में करीब 62 प्रतिशत लोगों को उपरोक्त योजनाओं के द्वारा रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा क्षेत्र के विस्तार के द्वारा अनुमान है कि 38 प्रतिशत शहरी बेरोजगारी को दूर किया जा सकेगा। ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नरेगा विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। यद्यपि बिहार में बिचौलियों के कारण ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग इससे अधिक लाभांवित नहीं हो सके हैं। यही कारण है कि आये दिन नरेगा के कार्यान्वयन की कठिनाइयों को दूर कर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के सशक्त योजना बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

भारत-विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में

21वीं शताब्दी के विश्व के सेवा क्षेत्र में भारतीय श्रम-पूंजी का अत्यधिक योगदान रहा है। पहले भी इंगलैंड के स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं में भारतीय श्रम-शक्ति का अत्यधिक योगदान था । इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिक में आज भी भारतीय श्रम-शक्ति के योगदान को सभी लोग स्वीकार करते हैं । श्रम-शक्ति के इसी योगदान के कारण पहले जहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए अभिशाप मानी जाती थी वहीं

दक्षता और ज्ञान की वृद्धि के कारण अब जनसख्या को मानव पूँजी के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। अर्थशास्त्र में जनसंख्या संबंधी विश्लेषण के बदले हुए परिवेश में मानवीय पूँजी (Human Capital) कहा जाने लगा है । आज भारत को विश्व का "अग्रणी युवा देश" कहा जाता है, क्योंकि अपेक्षाकृत यहाँ संपूर्ण जनसंख्या में ऊर्जावान युवा वर्ग की संख्या अधिक हो गई है । यह विकास के गति को बढ़ाने में मद्दगार साबित हो रहा है ।

उदारीकरण के कारण विश्व के सेवा क्षेत्र में जो विकास की गति आई है उसका लाभ सभी देशों को प्राप्त होने के अवसर आने लगे हैं । इस दृष्टिकोण से आज विश्व के औद्योगिक विकसित देश अपने उत्पाद एवं सेवाओं के विभिन्न कामों का सम्पादन वैसे देशों में कराने लगे हैं जहाँ सस्ती श्रम-शक्ति उपलब्ध होती है । उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं में से अधिकांश का उत्पादन चीन या कोरिया में होता है और भारत में भी डाबर कम्पनी अपने उत्पाद के कम मूल्य करने के लिए अपने पड़ोसी देश नेपाल में कारखाने खोल रखें हैं जहाँ श्रम-शक्ति सस्ती है । जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपनी सम्बन्धित नियमित सेवाएँ अपनी कम्पनी के जगह किसी बाहरी या विदेशी संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो ऐसी सेवाओं को Out-Sourcing (बाह्य स्रोती) कहा जाता है ।

बाह्य स्रोती (Out Sourcing)

जब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ या अन्य कंपनियाँ संबंधित नियमित सेवाएँ स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो उसे बाह्य स्रोती (Out Sourcing) कहा जाता है।

उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के वर्त्तमान युग में पूरा विश्व एक बाजार के रूप में उभर कर आया है । जिसके कारण न केवल एक देश की वस्तुएँ दुनिया के सभी बाजारों में सर्वसुलभ हो गई है, बल्कि उस वस्तु का उत्पादन क्षेत्र भी अलग-अलग हो गया है और देश में उत्पादन संस्थान बनी है जहाँ सस्ते मूल्य पर श्रम उपलब्ध है । जिससे एक ओर तो सस्ते श्रम वाले क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है वहीं अपेक्षाकृत कम लागत मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध होने लगी है ।

इन नीतियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ा है । भारत से आज तेजी से ध्वनि आधारित प्रक्रिया (voice based business process) जिसे बी० पी० ओ०

अथवा कॉल सेन्टर (call centre) कहा जाता है, अभिलेखांकन (recordkeeping), लेखांकन (accounting), बैंकिंग सेवाएँ, रेलवे पूछताछ, संगीत की रिकार्डिंग, पुस्तक शब्दांकन (Book Transcription), चिकित्सा संबंधी परामर्श (Medical Transcription), शिक्षण एवं शोध कार्य इत्यादि अनेक सेवाएँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (USA), यूरोपीय संघ जैसे कई विकसित देशों की कंपनियाँ प्रायः भारत की छोटी-छोटी कंपनियों या संस्थाओं से प्राप्त कर रही है। (Call-Centre) की कार्य-प्रणाली को चित्र संख्या 5.2 के द्वारा दिखाया गया है जहाँ एक केन्द्र में बैठकर दुनिया के विभिन्न देशों के उत्पादन एवं सेवा की क्रिया सम्पन्न होती है।

चित्र 5.2 कॉल सेन्टर

इन बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों या सरकार को भारत से इन सेवाओं या सूचनाओं को प्राप्त करना तुलनात्मक लागत के आधार पर काफी फायदेमंद है क्योंकि भारत में इन सेवाओं की तुलनात्मक लागत काफी कम है। इसका मुख्य कारण ही कुशल श्रमशक्ति की पर्याप्त उपलब्धता तथा निम्न मजदूरी दर है। भारत अपने श्रम की मेधाशक्ति, कुशलता, विशिष्टता एवं निम्न मजदूरी के कारण जो सेवाएँ विदेशों को उनकी कंपनियों के लिए भेजता है उसकी तुलनात्मक लागत काफी कम है। इसलिए इस क्षेत्र में व्यापक रोजगार मिल रही है। यही कारण है कि आउट

सोर्सिंग के मामले में भी भारत एक महत्त्वपूर्ण गंतव्य (Destination) बन गया है जो विश्व के अन्य देशों के रोजगार क्षेत्र में बहस का विषय हो गया है ।

सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएँ

सेवा क्षेत्र के विकास के लिए देश एवं राज्य स्तर पर बुनियादी सुविधाएँ का होना नितांत आवश्यक है । ये सुविधाएँ विकास धारा के 'रीढ़ की हड्डी' के समान है, इसकी अनुपस्थिति में विकास की क्रिया संभव नहीं है । देश या राज्य की सर्वांगीण प्रगति मूलतः कृषि, उद्योग एवं व्यापार पर निर्भर करती है और इनकी प्रगति आधारभूत संरचना अथवा बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर करती है । जिस देश अथवा क्षेत्र में बुनियादी सुविधााएँ अधिक होगी वहाँ औद्योगिक उत्पादन और रोजगार की वृद्धि होती है । उत्पादन और रोजगार के द्वारा ही सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है । संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे समृद्ध देशों में ज्ञान और शोध की सुविधाएँ अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में सेवा का विस्तार होता गया है जिसके कारण विश्व के सभी देशों से उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त किये हुए लोग का पलायन उन देशों में हुआ है । भारत के उच्चत्तम तकनीकी शिक्षा का केन्द्र IIT तथा उच्चत्तम व्यवसायिक शिक्षा केन्द्र IIM से निकले हुए युवा उन देशों में उच्चत्तम [illegible] रोजगार के लिए जाते हैं । उसी तरह भारत के बंगलोर शहर में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी ज्ञान के उपयोग के क्षेत्र के बढ़ने के कारण देश के सभी क्षेत्रों के उच्च सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्राप्त युवक रोजगार के लिए जाते हैं ।

दूसरी ओर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि राज्य भारत के काफी पिछड़े राज्यों में से माने जाते हैं । जिन्हें बीमारू (BIMARU) के नाम से जाना जाता है । इन राज्यों में बुनियादी सुविधा जैसे- बिजली, सिंचाई, यातायात एवं परिवहन, दूरसंचार इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है । BIMARU शब्द से नकारात्मक ध्वनि व्यक्त होने के कारण ये राज्य इस नाम से पुकारा जाना नहीं चाहते हैं । योजना आयोग भी इन राज्यों के लिए इस शब्दावली के प्रयोग को स्वीकार नहीं करती है । ऐसे भी इन राज्यों में खास कर

BIMARU	
BI	- बिहार
MA	- मध्य प्रदेश
R	- राजस्थान
U	- उड़ीसा

बिहार आर्थिक विकास के राह पर उन्मुख हुआ है जिसके कारण अब BIMARU शब्दावली के प्रयोग से लोग परहेज करते हैं। अर्थात् आर्थिक विकास का क्षेत्र कृषि, उद्योग अथवा सेवा कुछ भी हो इसके लिए बुनियादी सुविधाओं का होना परमावश्यक है।

इन सुविधाओं को और अच्छी तरह से समझने के लिए इन्हें निम्न चार्ट से दर्शाया गया है-

बुनियादी सुविधाएँ
या, आधारभूत ढाँचा

(Basic Infrastructure)

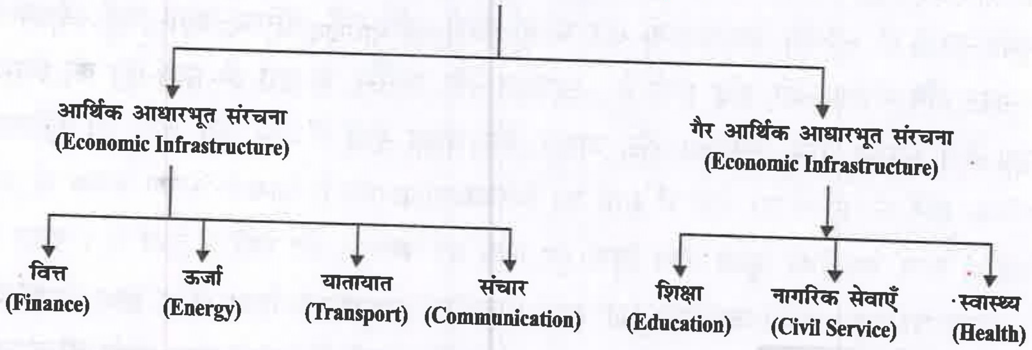

आर्थिक आधारभूत संरचनाएँ प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है । आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है । आर्थिक संरचना के अन्तर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है-

वित्त (Finance)- बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, अन्य सरकारी वित्तीय क्षेत्र ।

ऊर्जा (Energy)- कोयला, विद्युत, तेल, पेट्रोलियम, गैस, गैर पारंपरिक ऊर्जा एवं अन्य।

यातायात (Transport)- रेलवे, सड़कें, वायुयान, जलयान ।

संचार (Communication)-डाक, तार, टेलीफोन, टेलीसंचार (Telecommunication), मीडिया एवं अन्य ।

गैर आर्थिक संरचना से मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि कर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं अंततः आर्थिक विकास में सहायता प्रदान किया जाता है जो इस प्रकार है-

शिक्षा (Education)- अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर

माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं अन्य ।

स्वास्थ्य (Health)- अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम एवं अन्य ।

नागरिक सेवाएँ (Civil Services)- सामाजिक चेतना, सफाई एवं अन्य ।

भारत में बुनियादी सुविधाएँ को विकसित करने का परंपरा के तौर पर सरकार का ही पूरा दायित्व था, किन्तु सरकारी निवेश इस क्षेत्र में काफी कम था । इसी कारण 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के दौर में निजी क्षेत्र में भी स्वयं एवं सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारभूत संरचना के विकास में एक अहम् भूमिका निभानी शुरू कर दी है । आज संयुक्त रूप से आधारभूत संरचना में निवेश हो रहा है ज़िससे इसकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है । परन्तु ग्रामीण भारत में विश्व के उच्च तकनीकी उन्नति के बावजूद भी आधारभूत संरचनाओं की सुविधाओं का एकदम अभाव है । खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में तो बहुत ही कम बुनियादी सुविधाओं का विकास हो पाया है ।

सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका

आर्थिक विकास केवल वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन विस्तार से ही संभव नहीं है । इसके लिए मानव विकास एवं मानव पूँजी निर्माण नितांत आवश्यक है । मानव पूँजी भौतिक पूँजी से ज्यादा महत्त्वपूर्ण होता है। श्रमिकों की कुशलता, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य इत्यादि बढ़ाकर देश की उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है। आय तो मात्र एक विकल्प है, अर्थात् आय एक साधक है जबकि मानव विकास एक साध्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष मानव पूँजी निर्माण होता है। भौतिक पूँजी दृश्य होती है जबकि मानवीय पूँजी अदृश्य। बिना मानवीय पूँजी निर्माण के आर्थिक विकास कल्पना मात्र है।

अर्थात् मानव पूँजी निर्माण के लिए इनके प्रमुख घटकों पर विशेष ध्यान देना होगा। इनके प्रमुख घटक भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य हैं। इन घटकों के द्वारा मानव पूँजी को मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए सेवा क्षेत्र के विकास के लिए सर्वप्रथम इसे मजबूत बनाना होगा।

जब मानव पूँजी सबल हो जाता है तो इसकी महत्ता काफी बढ़ जाती है । अब सेवा क्षेत्र

के विकास के लिए इस मानव पूँजी पर निवेश करने की आवश्यकता होती है । वस्तुतः शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य स्थल, प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना में पूँजी निवेश करने के पश्चात् मानव पूँजी एक सशक्त साधन बन जाता है जिससे आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों का विकास संभव है ।

मानव पूँजी के प्रमुख घटक

- भोजन
- वस्त्र
- आवास
- स्वास्थ्य
- शिक्षा

अर्थात् मानव पूँजी का खास अभिप्राय एक देश में एक निश्चित समय सीमा पर कुशलता, क्षमता सुविज्ञता, शिक्षा तथा ज्ञान के भंडार से है । यह उन सभी प्रकार के पेशेवर तथा कुशल व्यक्तियों का स्टॉक अथवा भंडार है जो उत्पादन क्रियाओं से जुड़े हुए हैं ।

इस प्रकार मानव पूँजी निर्माण कौशल तथा सुविज्ञता प्राप्त अनुभवी व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने तथा प्राप्त करने की प्रक्रिया है । अच्छी मानव पूँजी; जैसे- वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, कुशल प्रशासक, समाज सेवी, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक एवं शिक्षाविद इत्यादि मानव पूँजी का उत्पादन करती है अर्थात् मानवीय संसाधनों से और अधिक मानव पूँजी के उत्पादन के लिए हमें मानव पूँजी में निवेश करने की आवश्यकता है । देश व राज्य का आर्थिक विकास शिखर पर पहुँचाने के लिए मानव पूँजी में निवेश के स्तर को ऊँचा उठाना होगा ।

हमारा मानव संसाधन कैसे सुदृढ़ एवं सशक्त हो इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम परिश्रम कर जनसंख्या के समग्र भाग को पर्याप्त भोजन, तन पर वस्त्र तथा सर छिपाने के लिए आवास, इन तीन प्रारंभिक आवश्कताएँ को पूरा कर देते हैं तो हमारी समस्या आधी हो जाती है। अब इन जनसंख्या को सबल बनाने हेतु इसके स्वास्थ्य पर जोर देने की आवश्यकता है। इस परिपेक्ष में यह कहा भी गया है कि "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है।" जब चार अवयव मिलकर मानव पर असर डालता है तो शिक्षा के माध्यम से उसे उस स्तर तक पहुँचाया जा सकता है जो कि आर्थिक विकास का एक सुदृढ़ सूचक बन जाएगा। इसी सूचक का ही देन पूँजी का निर्माण करेगा और आर्थिक विकास का परचम पूरे विश्व में लहरायेगा।

कुशल मानव पूँजी रोजगार के विभिन्न क्षेत्र को जन्म देता है । भारत वर्ष को आज इस

क्षेत्र में खास कर (Information Technology) सूचना तकनीकी में विश्व का अव्वल देश में गिनती की जा रही है । यहाँ के इंजीनियर कुशाग्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि के साबित हो रहे हैं । फलस्वरूप अपने देश के भीतर विदेशी पूँजी का आना अधिक हो गया है । फलतः हमारे देश में इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर काफी मात्रा में बढ़ी है । बंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली इत्यादि शहरें में सूचना एवं तकनीकी क्षेत्र का प्रमुख केन्द्र बिन्दु है जिसमें हजारों लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार की प्राप्ति हो रही है।

आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव

आर्थिक विकास किसी राष्ट्र एवं राज्य की सतत् प्रक्रिया है । जैसे-जैसे युगों में परिवर्तन होता जाता है वैसे-वैसे विकास की प्रक्रिया परिवर्तन के साथ बढ़ता जाता है । अर्थव्यवस्था से पुरानी चीजों का विलुप्त होना इसकी पहचान है । समय परिवर्तन के साथ व्यक्ति की माँग में परिवर्तन हो जाता है । व्यक्ति फैशन का शिकार हो जाता है । भारत में 1991 के वैश्वीकरण के पश्चात् विकास में काफी परिवर्तन देखने को मिलता हैं । औद्योगिक नीति का उदार होना व्यापार करनेवाले राष्ट्रों के बीच एक कड़ी प्रतिस्पर्धा ला दिया । लोगों को आसानी से विदेशी वस्तुओं की सेवा प्राप्त होने लगी । लोगों के बीच वस्तुओं की कीमतों के आधार पर गुणवत्ता परखने का अवसर मिल गया ।

वैश्वीकरण निजीकरण एवं उदारीकरण के कारण आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने लगा । लोगों को दूसरे राष्ट्र में जाकर रोजगार करने का खुला अधिकार प्राप्त हो गया । यद्यपि आर्थिक विचारकों का एक ऐसा भी समूह है जो मानता है कि वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण से आम आदमी का जीवन कठिन हो जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था पर अमीर देशों और अमीर लोगों का वर्चस्व हो जाएगा । कुछ हद तक इस आलोचना में बल भी है क्योंकि वैश्वीकरण और उदारीकरण से श्रम बाजार में श्रमिक संघटनों की भूमिका नगण्य हो जाएगी और आम लोग विकास के क्षेत्र में केवल मूक दर्शक ही रह जायेंगे । धीरे-धीरे इस मान्यता के लोगों के मत में बदलाव आ रहा है और लोग उदारवादी इन नीतियों के लाभ को समझने लगे हैं ।

विकसित राष्ट्र अमेरिका, स्वीट्जरलैंड, फ्रांस, रूस, जापान, चीन इत्यादि जगहों में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को काम करने का मौका मिल गया। तकनीकी क्षेत्र के वैज्ञानिकों में वृद्धि का समायोजन भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ की बुनियादी सुविधाएँ विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफी कम है।

वर्तमान मंदी के कारण सेवा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। उपभोक्ताओं की माँग बढ़ी है परन्तु उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इन उत्पादकों को लागत मूल्य से भी कम आय प्राप्त हो रही है। यही कारण है कि विकसित राष्ट्रों से तकनीकी वैज्ञानिकों को छटनी कर रोजगार से मुक्त कर दिया गया। इसका प्रभाव भारत के उन वैज्ञानिकों पर भी पड़ा जो दूसरे राष्ट्र में रोजगार कर रहे थे। उत्पादकों को उत्पादन क्रिया शिथिल करना पड़ गया। अत्यधिक घाटे के कारण विकसित राष्ट्रों में आत्महत्या करने जैसी घटनाएँ होने लगी। कई वित्तीय संस्थाओं को अमेरिका में अपनी सेवा बंद कर देनी पड़ी। इस प्रकार वर्तमान मंदी का प्रभाव विकसित राष्ट्रों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

भारत पर इसका असर कम पड़ा क्योंकि यहाँ की पूँजी बाजार काफी मजबूत अवस्था में अभी है। यहाँ के इंजीनियर आज भी बाह्य स्रोती (Out Sourcing) में लगे हुए हैं । खासकर भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफी मजबूत है और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियरों का स्थान अव्वल है। हमारा आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्त्तमान मंदी का असर हमारे देश पर कम पड़ा। भारत के बंगलोर जैसे शहर का सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गया है।

इस मंदी का प्रभाव बिहार राज्य पर भी कुछ पड़ा है। हमारे राज्य के जो इंजीनियर मंदी पड़े राष्ट्र में रोजगार में थे उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया फलस्वरूप नये–सिरे से इन्हें रोजगार हासिल करने की आवश्यकता आ गई। उन राष्ट्रों से जो आय हमारे राज्य में आते थे उसकी मात्रा घट गई।

इस प्रकार वर्तमान मंदी का प्रतिकूल प्रभाव विश्व के अधिकांश भागों पर पड़ा। कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या के अधिकांश लोगों पर भारत में मंदी का दुष्प्रभाव अधिक

नकारात्मक नहीं हुआ है । मंदी की वर्तमान दौर में इस बात की आवश्यकता होने लगी है कि बिहार में कृषि और कृषि जनित उद्योगों को अत्यधिक मजबूत बनाया जाए । हम देख चुके हैं कि वर्तमान मंदी का बुरा प्रभाव भारत पर उतना अधिक नहीं पड़ा है । जिसका इसका बुरा प्रभाव विकसित देशों पर पड़ा है । भारतीय पूँजी बाजार की मजबूती, मानवीय श्रम की उच्च दक्षता एवं विशाल श्रमशक्ति के कारण यह आशा व्यक्त की जाने लगी है कि 21वीं शताब्दी में भारत विकास की उच्चतम सीमा पर पहुँचकर विश्व के अत्यधिक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा ।

आगे आने वाले वर्षों में सामान्य रूप से संपूर्ण भारत में और विशेष रूप से बिहार में सेवा क्षेत्र के विकास की अपार सम्भावनाएँ हैं । 2020 तक चीन सहित संपूर्ण अमेरिका और यूरोप के देशों में बूढ़ों की संख्या युवकों की तुलना में अधिक होगी वहीं भारत विशेष रूप से युवाओं का देश होगा जहाँ से कुशल श्रमिकों की Out Sourcing (बाह्य स्रोती) संपूर्ण विश्व में होगा ।

सारांश

- रोजगार एवं सेवाएँ एक-दूसरे के पूरक हैं । रोजगार एवं सेवाओं की प्राप्ति आर्थिक विकास के क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है । आर्थिक विकास के मुख्य रूप से तीन क्षेत्र हैं– (क) कृषि क्षेत्र (ख) उद्योग क्षेत्र (ग) सेवा क्षेत्र ।
- ''सेवा क्षेत्र'' को ही आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है । सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में 55.1 प्रतिशत योगदान है जबकि कृषि एवं उद्योग में मात्र 44.9 प्रतिशत ।

  'सेवा क्षेत्र' का विकास कृषि एवं उद्योग में पायी जानेवाली अनिश्चितता के कारण हुआ।
- प्रमुख सेवा क्षेत्र– (क) सरकारी सेवा क्षेत्र

  (ख) गैर सरकारी सेवा क्षेत्र
- **(क) सरकारी सेवा क्षेत्र–** सैन्य सेवाएँ, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा, दूर संचार सेवा, रेल सेवा, वायुयान सेवा, बस सेवा, कृषि सेवा

एवं अन्य प्रमुख हैं ।

- **(ख) गैर सरकारी सेवा क्षेत्र**– दूर संचार सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, मौल सेवा, स्वरोजगार सेवा एवं अन्य प्रमुख हैं ।
- सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं में कुछ ऐसी सेवाएँ हैं जिसका विकास सरकार एवं निजी दोनों के ही सहयोग से किया जा रहा है; जैसे– यातायात सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग सेवा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि प्रमुख उदाहरण हैं ।
- **सेवा क्षेत्र का महत्त्व**– सेवा एवं रोजगार एक ही तराजू के दो पलड़ों के समान हैं ।
- **रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की भूमिका**– सेवा का क्षेत्र सरकारी हो अथवा गैर सरकारी, दोनों ही परिस्थितियों में रोजगार का सृजन होता है । सरकारी क्षेत्र के सहयोग से रोजगार का सृजन निम्न सेवाओं के द्वारा किया जा रहा है– काम के बदले अनाज-2004, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम-1980, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम- 1983, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम-1980, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम-1980, जवाहर रोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, नरेगा इत्यादि ।
- **भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में**
- बाह्य-स्त्रोती (Out Sourcing)– जब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ या अन्य कंपनियाँ संबंधित नियमित सेवाओं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाए किसी बाहरी या विदेशी स्त्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो उसे बाह्य-स्त्रोती (Out Sourcing) कहा जाता है ।
- सेवा क्षेत्र की बुनयादी सुविधाएँ– (क) आर्थिक (ख) गैर आर्थिक

  (क) आर्थिक– वित्त, ऊर्जा, यातायात एवं संचार

  (ख) गैर आर्थिक– शिक्षा, नागरिक सेवाएँ एवं स्वास्थ्य
- **मानव पूँजी के प्रमुख घटक** – भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा ।
- **आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव** – विकसित राष्ट्रों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जबकि भारत पर कम ।

  बिहार राज्य पर अन्य राज्यों [illegible] प्रभाव पडा है।

प्रश्नावली

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Question)

I. सही विकल्प चुनें।

1. आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है ?

(क) कृषि क्षेत्र (ख) विज्ञान क्षेत्र (ग) शिक्षा क्षेत्र (घ) सेवा क्षेत्र

2. मानव पूँजी के प्रमुख घटक कितने हैं ?

(क) 6 (ख) 4 (ग) 5 (घ) 8

3. कौन बीमारु (BIMARU) राज्य नहीं है ?

(क) बिहार (ख) मध्य प्रदेश (ग) कर्नाटक (घ) उड़ीसा

4. कौन-सी सेवा गैर सरकारी है ।

(क) सैन्य सेवा (ख) वित्त सेवा (ग) मॉल सेवा (घ) रेल सेवा

5. ऊर्जा के मुख्य स्त्रोत क्या है ?

(क) कोयला (ख) पेट्रोलियम (ग) विद्युत (घ) इनमें से सभी

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short- Answer Questions)

1. Out Sourcing किसे कहते हैं ?
2. सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) से जुड़े पाँच सेवा क्षेत्र को बतलाएँ ।
3. सरकारी सेवा किसे कहते हैं ?
4. गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं ?
5. आधारभूत संरचना किसे कहते है ?
6. 'रोजगार' और 'सेवा' में क्या संबंध है ?
7. आर्थिक संरचनाएँ का क्या महत्त्व है ?
8. मंदी का असर भारत में क्या पड़ा ?

9. वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long- Answer Questions)

1. सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखें ।
2. विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है उदाहरण सहित लिखें ।
3. सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किये गए हैं, वर्णन करें ।
4. गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है, उदाहरण देकर लिखें।
5. वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा लिखें ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर

I. 1. (घ) 2. (ग) 3. (ग) 4. (ग) 5. (घ)

*